कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक

"छोटे पैमाने के किसानों के वित्तपोषण में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ" विषय पर
दिनांक 20 मई 2021 को आयोजित
CAB-APRACA संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोगी मिशन के भाग के रूप में, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे और एशिया पैसिफिक ग्रामीण और कृषि ऋण एसोसिएशन (एपीआरएसीए), बैंकॉक, थाईलैंड द्वारा "छोटे पैमाने के किसानों के वित्तपोषण में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ" विषय पर 20 मई 2021 को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संयुक्त संगोष्ठी का आयोजन सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन किया गया और इसमें 196 प्रतिनिधियों (88 भारत से और 108 विदेशों से) ने भाग लिया ।

संगोष्ठी का उद्देश्य एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों, केंद्रीय बैंकरों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करना था ताकि छोटे पैमाने पर खेती करनेवाले किसानों को वित्तपोषित करने के लिए उनके व्यावहारिक अनुभव, नवाचार और उत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श किया जा सके।

श्री वी जी सेकर, मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य, सीएबी ने अपने स्वागत संबोधन में भारत और एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर खेती करनेवाले किसानों के भूमि धारण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि की स्थिति की संक्षिप्त जानकारी दी और छोटे पैमाने पर खेती करने वाले कृषकों के वित्तपोषण के लिए आरबीआई द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने संगोष्ठी के प्रतिनिधियों से छोटे पैमाने पर खेती करनेवाले किसानों के वित्तपोषण की सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने का अनुरोध किया, ताकि आपस में सीख ली जा सकें और उनका अनुकरण किया जा सकें|

नाबार्ड के अध्यक्ष और APRACA के अध्यक्ष डॉ जी आर चिंताला ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने वैश्विक स्तर पर छोटे पैमाने के किसानों के वित्तपोषण की चुनौतियां और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत में कृषि क्षेत्र ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने COVID-19 महामारी के दौरान पॉजिटिव वृद्धि दर्ज की। उन्होंने एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के देशों में कृषि उत्पादन में छोटे और सीमांत किसानों की प्रमुख हिस्सेदारी का

उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संस्थागत स्रोतों के माध्यम से कृषि-ऋण प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करने के मामले में एशिया-प्रशांत देशों में भारत एकमात्र अपवाद है। उन्होंने इस ऋण प्रवाह के लिए भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा किए गए नीतिगत उपायों और पहलों की श्रृंखला जैसे कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण पर दिशानिर्देश, केसीसी के अंतर्गत फसल ऋण, ब्याज सहायता योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषि उत्पादों के संग्रहण और बेहतर मूल्य की खोज के लिए किसान उत्पादक संगठन, ऋण गारंटी योजनाएं, जेएलजी प्रणाली में टेनेंट किसान वित्तपोषण आदि को श्रेय दिया। उन्होंने उभरती हुई अवधारणाओं जैसे कि, कृषि मशीनरी और उपकरणों का उबरायजेशन , स्टार्ट अप के माध्यम से डिजिटल समाधान और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के बारें अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कहा कि इससे आम तौर पर किसानों और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के सम्मुख आनेवाली जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी ।

संगोष्ठी में दो तकनीकी सत्र - "एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से छोटे किसानों के वित्तपोषण के लिए नवोन्मेषी रणनीतियाँ" और "कृषि मूल्य श्रृंखला की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के लिए ऋण मॉडल" शामिल थे।

पहले तकनीकी सत्र का संचालन श्री नायजेल ब्रेट, निदेशक, एशिया पैसिफिक प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी), रोम द्वारा किया गया। इस सत्र के पैनल में शामिल थे : (i) श्री एलिसन पिडिक, सहायक गवर्नर, बैंक ऑफ पापुआ न्यू गिनी सेंट्रल बैंक, पीएनजी, (ii) श्री फिलिप फारेनहोल्ट्ज, निवेश अधिकारी, आईएफसी / जीएएफएसपी, सिंगापुर और (iii) श्री मुरली कृष्णा, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत। संगोष्ठी में कुछ विषय/मुद्दों पर भी चर्चा की गई जिनमें (i) छोटी जोत के लिए अभिनव वित्तपोषण मॉडल, (ii) प्रौद्योगिकी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्वीकरण स्तर, बाजार पहुंच, जोखिम कम करना और किसानों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता, (iii) प्रौद्योगिकी स्टैक, कार्यान्वयन और साझेदारी का निर्माण शामिल थे। श्री ब्रेट ने चर्चा का समापन करते हुए कहा कि कृषि-प्रौद्योगिकी को अपनाने, बाजार पहुंच और जोखिम कम करने जैसे क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न प्लेयर जैसे, सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, बैंक और प्रौद्योगिकी प्रदाता, क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्टेकहोल्डरों के बीच लागत साझाकरण तंत्र की व्यवस्था होती तो नए उत्पाद/सेवाओं लागत कम होती।

दूसरे तकनीकी सत्र का संचालन श्री सीतारामचंद्र मचिराजू, वरिष्ठ कृषि-व्यवसाय विशेषज्ञ, पूर्वी एशिया और पैसिफिक क्षेत्र, विश्व बैंक, बीजिंग द्वारा किया गया। इस सत्र के पैनलिस्ट थे (i) सुश्री एमिली तामायो, सिनियर वाइस प्रेसिडेंट (ऋण कार्यक्रम प्रबंधन समूह), लैंड बैंक ऑफ फिलीपीन्स, फिलीपीन्स और (ii) श्री अनिल कुमार एसजी, सीईओ, समुन्नती फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, भारत। अपने प्रारंभिक उदबोधन में, श्री माचिराजू ने खाद्य प्रशासन,

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और स्थायी रूप से आपूर्ति और स्थिर बाजार सुनिश्चित करने के लिए मूल्य श्रृंखला आर्किटेक्चर की वांछनीय विशेषताओं पर विचार-विमर्श किया। पैनलिस्टों ने उनके द्वारा स्थापित मूल्य श्रृंखलाओं और वित्तीय मध्यस्थता तथा उत्पादों पर प्रेजेंटेशन दिया। श्री अनिल कुमार ने अपनी संस्था द्वारा कार्यान्वित की गई मिर्च मूल्य श्रृंखला जैसेकि संगठित उत्पादन, एकत्रीकरण, पूर्व निर्धारित बाजार और मूल्य, किसानों के लाभ, सेवाओं की लागत और वित्तीय मध्यस्थता आदि के बारें में विस्तार जानकारी दी। सुश्री एमेली ने सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों और अन्य लिंकेज का समर्थन करने के साथ-साथ अपने बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। मॉडरेटर के साथ-साथ प्रतिनिधियों के कुछ प्रश्नों के प्रत्युत्तर में पैनलिस्टों ने मूल्य श्रृंखला की प्रकृति, उधार उत्पादों के प्रकार, प्रौद्योगिकी की सोर्सिंग, जोखिम कम करना, वैकल्पिक संपार्श्विक, उत्पाद का मूल्य निर्धारण और लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया। श्री मचिराजू ने चर्चा का समापन किया और पैनलिस्टों को सफलतापूर्वक कृषि-मूल्य श्रृंखला स्थापित करने और संपार्श्विक के बिना उपयुक्त उधार मॉडल विकसित करने के लिए बधाई दी।

श्री अनिल कुमार शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने समापन संबोधन में व्यापक प्रासंगिकता वाले विषय पर संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए सीएबी और एपीआरएसीए के प्रयासों की सराहना की। इस विषय पर अपने विचार करते हुए कार्यपालक निदेशक महोदय ने सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से कृषि में ऋण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और आरबीआई द्वारा की गई पहल की संक्षिप्त जानकारी दी। तत्पश्चात, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अग्रणी बैंक योजना, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण, केसीसी, सूक्ष्म वित्त गतिविधियां, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, डिजिटल वित्तीय उत्पादों प्रारम्भ, एफपीओ आदि. जैसी पहलों और भारतीय कृषि क्षेत्र पर उनके प्रभाव की जानकारी दी। आगे उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश के अनुरूप नीतिगत दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है और उन्होंने आशा व्यक्त की, कि संगोष्ठी के विचार-विमर्श से कई संभावित नीतिगत विकल्प सामने आएंगे जो विश्व भर के छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।

संगोष्ठी के निदेशक सर्वश्री एन मधुमूर्ति, महाप्रबंधक और ए एस पिल्लई, महाप्रबंधक, सीएबी और डॉ. प्रसून कुमार दास, महासचिव, एपीआरएसीए थे।

इस वर्चूअल कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें नीचे दी गई है:

College of Agricultural Banking
Reserve Bank of India

CAB-APRACA Joint International Symposium on 'International Best practices in Financing Smallholder Farmers' held on May 20, 2021

As a part of its collaborative mission with reputed institutions, the College of Agricultural Banking (CAB), Reserve Bank of India, Pune and Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), Bangkok, Thailand jointly organized an International Symposium on '**International best practices in financing small holder farmers'** on May 20, 2021. The Joint Symposium was organized online through CISCO WebEx platform and was attended by 196 delegates (88 from India and 108 from overseas).

The objective of the symposium was to provide a platform for the financial institutions, central bankers, academicians, policy makers and other stakeholders in the Asia-Pacific Region to deliberate and share their practical experiences, innovations and good practices to finance small holder farmers.

In his welcome address, Shri V G Sekar, CGM & Principal, CAB, presented a brief account of the agricultural situation with focus on small farmer holdings in India and in the Asia-Pacific Region, and highlighted various policy initiatives of RBI for financing small holder farmers in India. He requested the delegates of the Symposium to share the best practices and innovations in financing smallholder farmers for mutual learning and emulation.

Dr G R Chintala, Chairman, NABARD & Chairman, APRACA, inaugurated the Symposium. In his inaugural address, he focused on the challenges and opportunities in financing small holder farmers globally. He mentioned that agriculture sector was the only sector in India that had registered positive growth during the COVID-19 pandemic. He highlighted the dominant share of small and marginal farmers in agricultural production in the countries of Asia and Pacific Region. He stated that India is the sole exception amongst Asia-Pacific countries as far as providing a large share of agri-credit flow from institutional sources. He attributed this credit flow to a series of policy measures and initiatives taken by Government

of India, RBI & NABARD, viz., Priority Sector Lending guidelines, crop loans under KCC, interest subvention scheme, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Farmer Producers' Organisations for collectivization and better price discovery for the farm produce, credit guarantee schemes, tenant farmer financing in JLG mode, etc. He also touched upon the emerging ideas viz., uberisation of farm machinery & equipment, digital solutions through Start Ups and climate change adaptation measures which he opined, would help mitigating the risks encountered by farmers in general and small and marginal farmers, in particular.

The Symposium comprised of two technical sessions viz., "Innovative strategies for financing small farmers through banking system in the Asia Pacific Region" and "Lending models to promote efficiency in agricultural value chain".

The first technical session was moderated by Mr. Nigel Brett, Director, Asia Pacific Division, International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome. The panelists for the session were (i) Mr. Ellison Pidik, Assistant Governor, Bank of Papua New Guinea Central bank, PNG, (ii) Mr. Phillip Farenholtz, Investment Officer, IFC/ GAFSP, Singapore and (iii) Mr. Murali Krishna, General Manager, Bank of Baroda, India. Some of the topics/issues discussed pertained to (i) innovative financing models for small holdings, (ii) acceptance level of digital platforms for technology, market access, risk mitigation and need for capacity building of farmers, (iii) technology stack, implementation and building partnerships. Summarizing the discussions, Mr. Brett expressed that various players viz., government agencies, NGOs, banks and technology providers were working together passionately in various parts of the region to address the challenges faced by small and marginal farmers, in the areas of agri-technology adoption, market access and risk mitigation. He also opined that the new products/ services would prove cost effective, if the system of cost sharing mechanism amongst stakeholders was in place.

The second technical session was moderated by Mr. Sitaramachandra Machiraju, Sr. Agri-business specialist, East Asia & Pacific Region, World Bank, Beijing. The panelists of the session were (i) Ms. Emellie Tamayo, Sr. Vice President (Lending Programmes Management Group), Land Bank of Philippines, Philippines and (ii) Shri Anil Kumar SG, CEO, Samunnati Financial Intermediation and Services Pvt Ltd., India. In his initial remarks, Mr. Machiraju deliberated on the food governance, disruptions in supply chain,

and the desirable features of value chain architecture to ensure sustainable supplies and stable markets. The panelists made presentations on the value chains established by them and financial intermediation and products. Mr. Anil Kumar elaborated on the details of chilli value chain viz., organised production, aggregation, predetermined markets and prices, benefits to farmers, cost of services & financial intermediation, etc. implemented by his institution. Ms. Emellie presented a detailed account of financial products and services offered by her bank along with supporting government policies/programmes and other linkages. Responding to some queries from the moderator as well as from the delegates, the panelists clarified on various issues relating to the nature of value chain, types of lending products, sourcing of technology, risk mitigation, alternative collaterals, pricing of product and cost benefit analysis. Mr. Machiraju summarized the discussions and complimented the panelists for successfully establishing agri-value chain and for evolving suitable lending models *sans* collateral.

In his valedictory address, Shri Anil Kumar Sharma, Executive Director, Reserve Bank of India appreciated the efforts of CAB & APRACA in organizing the Joint International Symposium on a subject of great relevance with an outreaching scale. Dwelling upon the subject, the Executive Director gave a snapshot of the initiatives of Government of India and RBI to boost credit to rural areas in general and agriculture, in particular. Thereby, he touched upon the host of initiatives and their impact on the Indian agricultural sector, such as Nationalization of banks, Lead Bank Scheme, Priority Sector Lending, KCC, microfinance movement, financial inclusion and literacy, introduction of digital financial products, FPOs, etc. While adding that the policy guidelines were being revised in tune with the changing environment, he was positive that the deliberations would yield many possible policy options that would positively impact the livelihoods of small and marginal farmers across the globe.

The Symposium Directors were S/Shri N Madhumurthy and A S Pillai, General Managers, CAB and Dr. Prasun Kumar Das, Secretary General, APRACA.

Some snapshots of the virtual event are presented below:

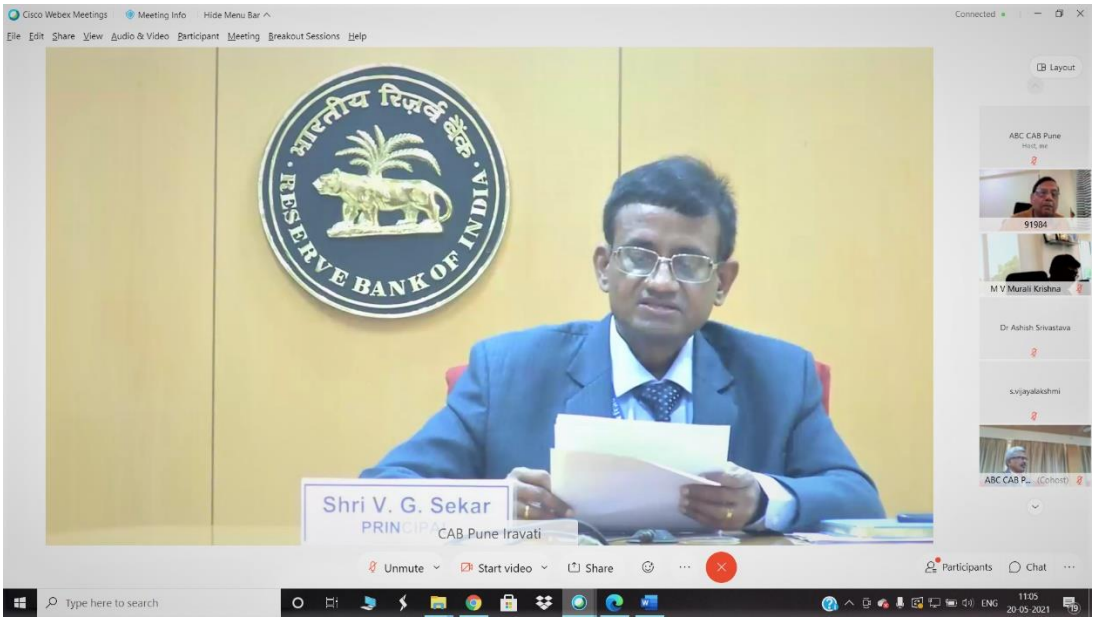

Welcome Address by Shri V G Sekar, CGM & Principal, CAB

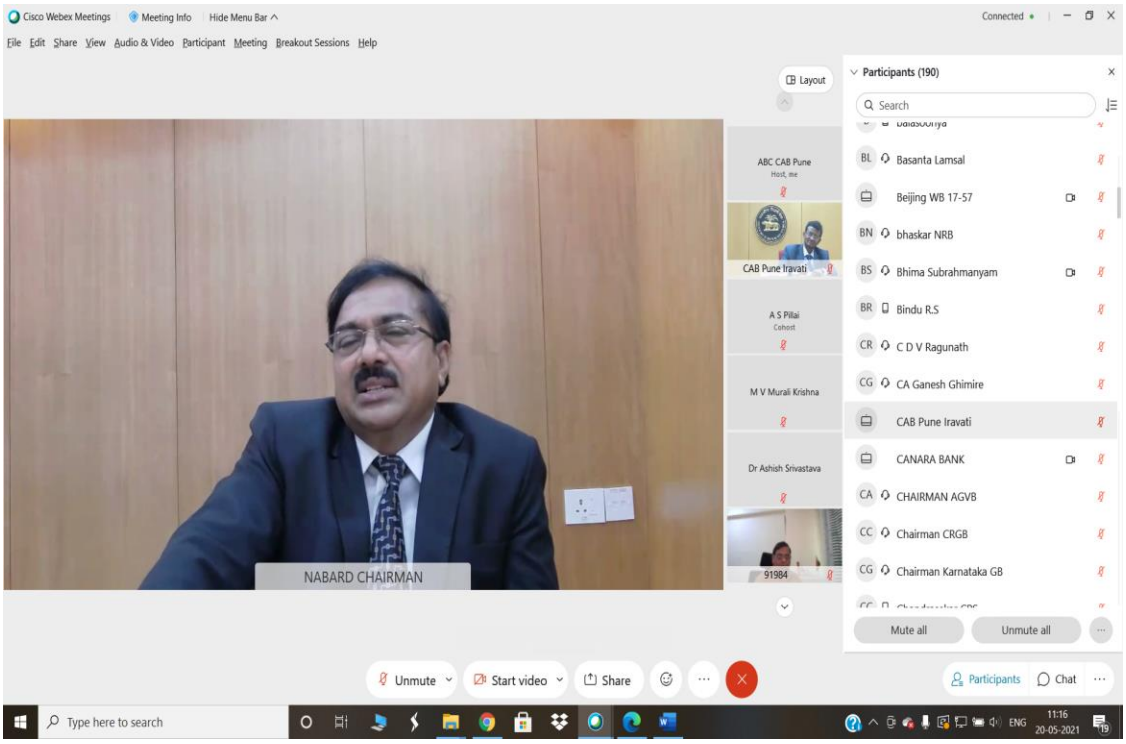

Inaugural Address by Dr. G R Chintala, Chairman, NABARD & Chairman, APRACA

First Technical Session moderated by Mr. Nigel Brett, IFAD, Rome

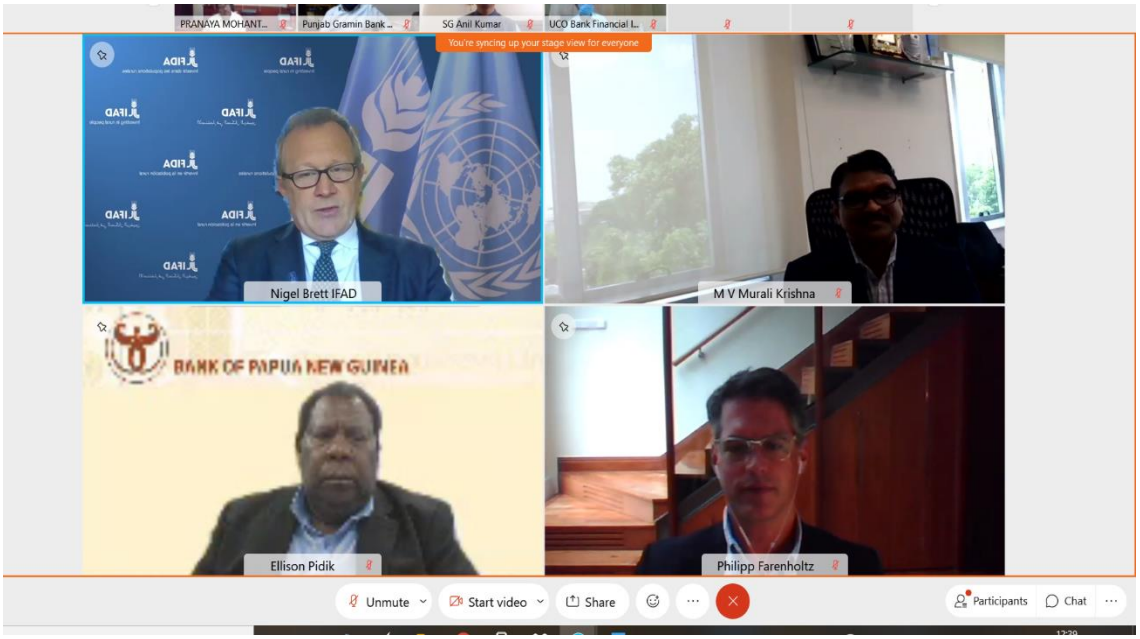

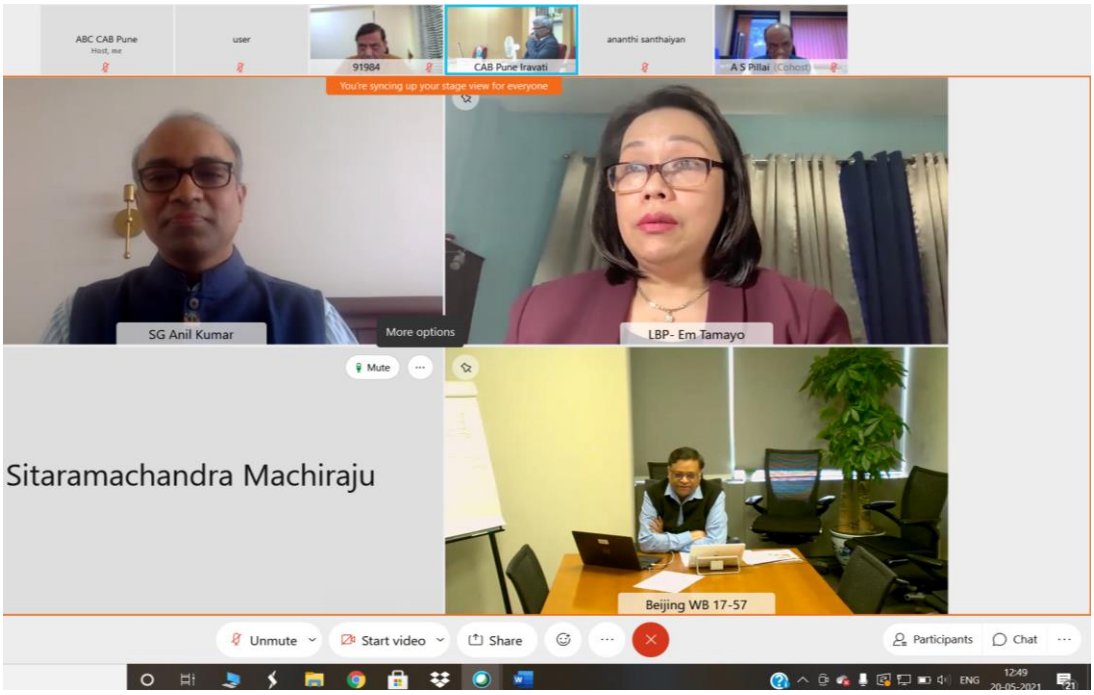

Second Technical Session moderated by Mr. Sitaramachandra Machiraju, World Bank, Beijing

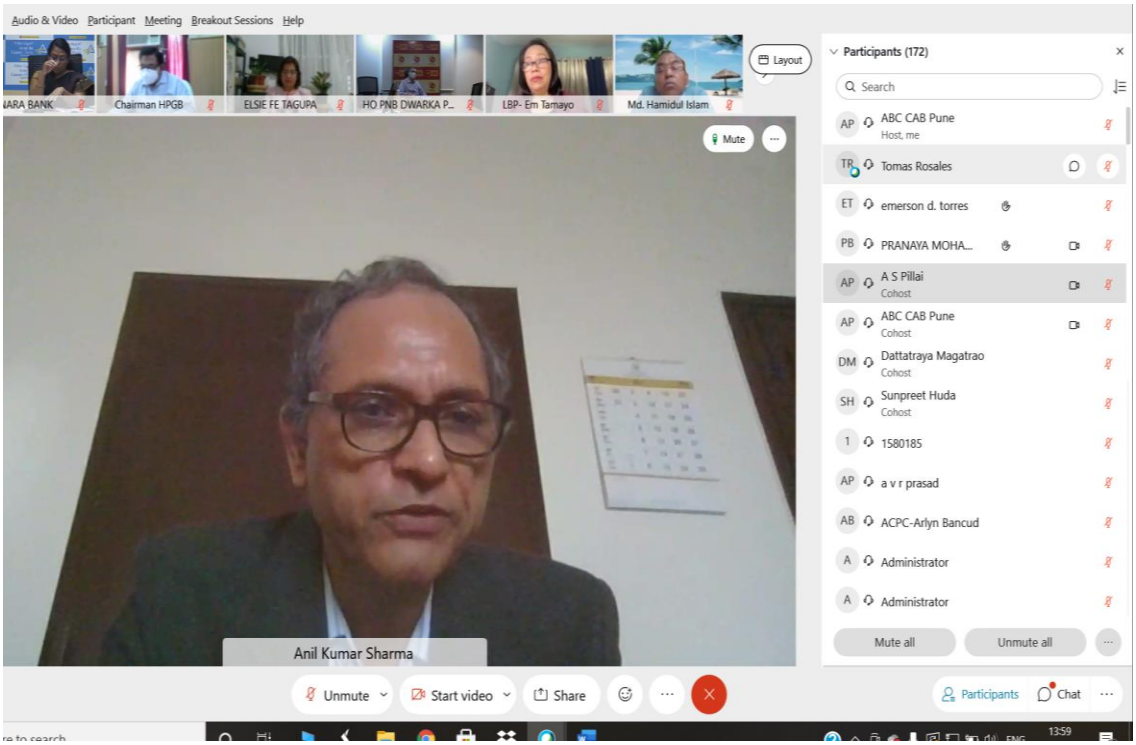

Valedictory Address by Shri Anil Kumar Sharma, Executive Director, RBI

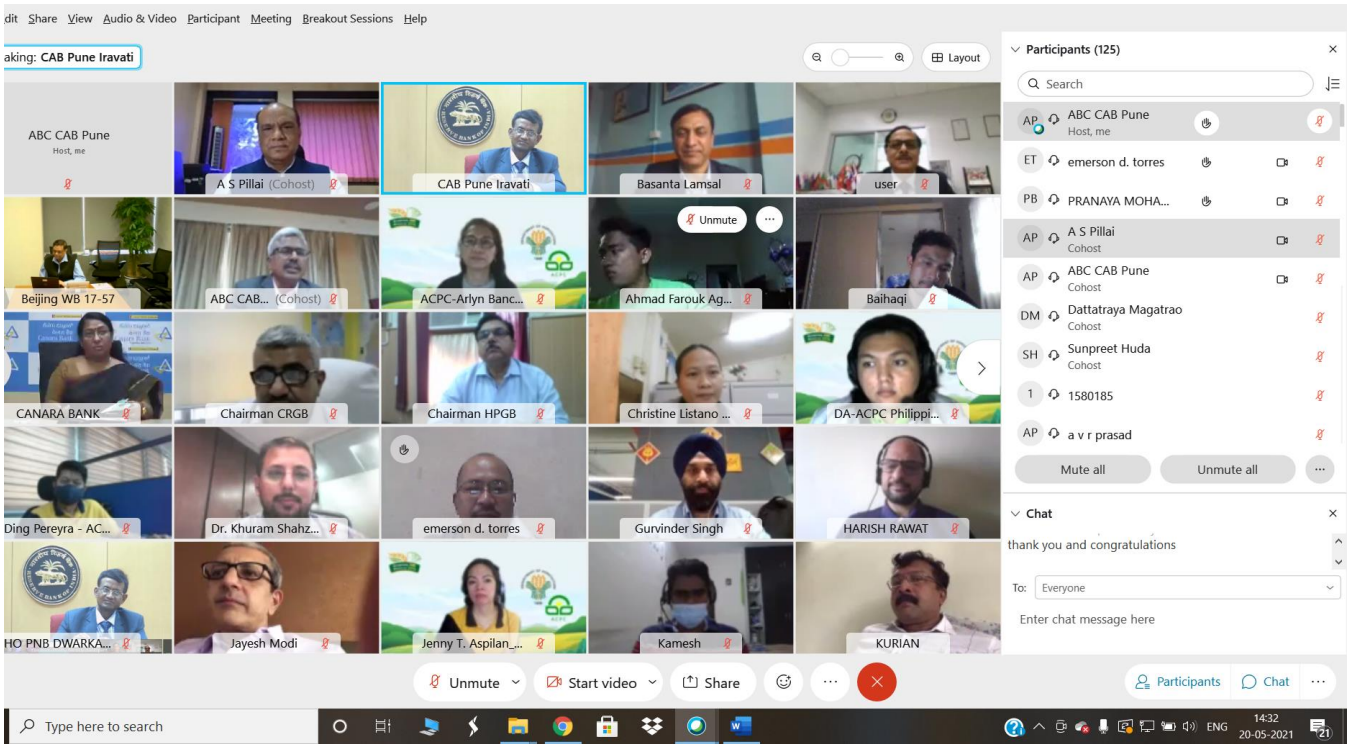

Delegates from India and Overseas